



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092024-257563
CG-DL-E-27092024-257563

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3896]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 27, 2024/आश्विन 5, 1946

No. 3896]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 27, 2024/ASVINA 5, 1946

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

का.आ. 4254(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आवंटन) (तीन सौ सतहत्तरवां संशोधन) नियम, 2024 है।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे।
- भारत सरकार (कार्य-आवंटन) नियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में,-
 - “संचार मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “क. दूरसंचार विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 1 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

“1क. टेलीकॉम नेटवर्कों की सुरक्षा से संबंधित मामले।”;
 - “इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 5क के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

“5ख. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) (समय-समय पर यथा संशोधित) में सौंपे गए साइबर सुरक्षा से संबंधित मामले और साइबर सुरक्षा पर अन्य मंत्रालयों/विभागों को सहयोग करना।”

(iii) “गृह मंत्रालय” शीर्षक के अधीन, “क. आंतरिक सुरक्षा विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 36 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

“36क. साइबर अपराध से संबंधित मामले.”;

(iv) “राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय” शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 2 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

“3. साइबर सुरक्षा के लिए समग्र समन्वय और रणनीतिक निदेश प्रदान कराना।”

द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/21/5/2024-मंत्रि.]

सतेन्द्र सिंह, अपर सचिव

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2024

S.O. 4254(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (Three Hundred and Seventy Seventh Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE, -

(i) under the heading “MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SANCHAR MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS (DOOR SANCHAR VIBHAG)”, after entry 1, the following entry shall be inserted, namely:-

“1A. Matters relating to security of telecom networks.”;

(ii) under the heading “MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY (ELECTRONIKI AUR SOOCHANA PRAUDYOGIKI MANTRALAYA)”, after entry 5A, the following entry shall be inserted, namely:-

“5B. Matters relating to Cyber Security as assigned in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) (as amended from time to time) and support to other Ministries / Departments on Cyber Security.”;

(iii) under the heading “MINISTRY OF HOME AFFAIRS (GRIH MANTRALAYA)”, under the sub-heading “A. DEPARTMENT OF INTERNAL SECURITY (ANTRIK SURAKSHA VIBHAG)”, after entry 36, the following entry shall be inserted, namely:-

“36A. Matters relating to Cyber Crime.”;

(iv) under the heading “NATIONAL SECURITY COUNCIL SECRETARIAT (RASHTRIYA SURAKSHA PARISHAD SACHIVALAYA)”, after entry 2, the following entry shall be inserted, namely:-

“3. To provide overall coordination and strategic direction for Cyber Security.”.

Droupadi Murmu

President

[F. No. 1/21/5/2024-Cab.]

SATENDRA SINGH, Addl. Secy.